यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने सवाल किया था उसके दो भाग हैं—पहला यह कि यह पब्लिक सेक्टर की कंपनी है कि नहीं, उसका जवाब दीजिए और दूसरा यह कि जो-जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए, ये टाइम पर मुकम्मल हुए या नहीं और ठीक तरीके से मुकम्मल हुए या नहीं । अगरचे ये ठीक तरह से और टाइम पर मुकम्मल हुए तो इनका रिव्यू क्यों किया जा रहा है ?

श्री देवी लाल : मैं ऑनरेबल मेंबर को जवाब दे रहा हू कि पब्लिक सैक्टर कंपनी है इसलिए जो बार-बार यह घोटाला हुआ है, यह तो प्रभु की लीला है । मैं उसकी पड़ताल कर रहा हूं . . . मैं जब रिपोर्ट हाउस के सामने रखूगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी । मैं अभी इसी काम में लगा हुआ हूं ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : अध्यक्ष महाराज, मेरी मदद कीजिए । ऐसे नहीं लेगा ।

**Doubling of railway tracks in Kerala**

*264. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are taking any steps to speed up the work of doubling the railway tracks in Kerala keeping in view the inadequate train facilities in Kerala; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

**Statement**

Yes, Sir. However, the train services in Kerala are considered adequate for the present level of passenger traffic.

In Kerala, the section between Palghat and Ernakulam is already doubled. Between Ernakulam and Kayankulam, an alternative B.G. line has been proposed for construction. Of this, Ernakulam-Alleppey (57 km) has already been commissioned on 15.10.1989. Work on Alleppey-Kayankulam (43 km) is in progress and when completed, it will provide two lines between Ernakulam Kayankulam. Doubling between Kayankulam and Quilon (41 km) was approved in the Budget for 1989-90 and between Quilon and Trivandrum Central (65km) has been included in the Budget for 1990-91. A survey for doubling of Shoranur-Mangalore (307 km) section has also been included in the Budget for 1990-91.

( *Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Balanandan, you don't want to ask a supplementary? (*Interruptions*) It is all right. Question No. 265. (*Interruptions*)

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Sir, I wanted to ask a supplementary on Question No. 264.. How can you go to the next. . .(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Sir,. . .

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. (*Interruptions*) Please take your seat. I am hearing nobody now. I am going by Rules. These are the Rules. These are the Rules. These are the Rules. He did not want to put a supplementary. I can't force him.

Next question. Question No. 265.

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में संचालन समिति की नियुक्ति**

*265. श्री राम जेठमलानी :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :†

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण को वर्तमान

† सभा में यह प्रश्न सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा द्वारा पूछा गया ।

प्रणाली के संबंध में एक संचालन समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संचालन समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं और क्या इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कोई भावी कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) योजना आयोग द्वारा एक संचालन दल का गठन किया गया था ।

(ख) से (घ) संचालन दल ने आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई हैं :—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक लक्ष्योन्मुख दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि राजसहायता के लाभ केवल गरीब लोगों को प्राप्त हों ।

(2) राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी उचित दर दुकानधारियों के ऊपर छोड़ने के स्थान पर सीधे उचित दर दुकानों को देने की व्यवस्था करने पर विचार करें ।

(3) मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आदि जैसी एजेंसियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के संबंध में खुली बाजार दखल कार्यवाही फिर से शुरू की जाए ।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों में मोटे अनाजों को एक मद के रूप में शामिल किया जाए ।

(5) विभिन्न राज्यों में राशन के पैमानों को युक्तियुक्त बनाया जाए ।

(6) राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियत खाद्यान्नों पर बिक्री कर/चुंगी आदि नहीं लगाई जाए ।

(7) समेकित आदिवासी विकास क्षेत्रों में, विशेष रूप से राजसहायतायुक्त खाद्यान्नों को अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति जारी रखी जाए और उसका दूसरे क्षेत्रों में विस्तार किया जाए जहां अधिकांश संख्या में कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं । परन्तु ऐसे क्षेत्रों में उन वर्गों को इसके अंतर्गत न लाया जाए जो गरीब नहीं हैं ।

(8) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जहां अपेक्षित आधार ढांचे संबंधी सुविधाएं जैसे भंडारण, ढुलाई आदि पर्याप्त नहीं है वहां उनका और विकास किया जाए ।

(9) साफ्ट कोक, मिट्टी के तेल तथा कंट्रोल के कपड़े को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएं ।

संचालन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा ।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know when the report was submitted by the Steering Committee to the Planning Commission. How long ago was that? Is the Planning Commission now steering these recommendattons or are they lying in cold storage with the Planning Commission?

**श्री राम विलास पासवान** : सभापति जी, 29-7-88 को इसका गठन किया गया था और जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक पंचवर्षीय योजना शुरु होने से पहले बहुत सारी स्टीरिंग कमेटियां बनाई जाती हैं और यह अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को देती हैं जो

उस पर विचार करता है । जैसा कि मैंने कहा इस बार भी गठित की गई समितियों की सिफारिशों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Still I have not got the answer as to when the steering Committee gave the report to the Planning Commission. Is it in 1988 or when?

SHRI RAM VILAS PASWAN: It is in 1989.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: If it is so, then has the Planning Commission taken any action on it during the whole year or has it made any recommendations to the Government? After going through these recommendations, would they agree or disagree? I would like to know that.

**श्री राम विलास पासवान :** सभापति जी, ऐसा होता है कि योजना आयोग स्टीयरिंग कमेटी बनाती है, विभिन्न ग्रुप्स बनाती है जिनमें एक नहीं काफी लोग रहते हैं । वह अपनी सिफारिशें पेश करते हैं । यह सिफारिश पेश की गई है । योजना आयोग उस पर, विचार कर रही है। योजना आयोग उनको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकती है । रिपोर्ट दे दी गई है, यह मैंने आपको बता दिया है ।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: You are waiting for the Planning Commission to give their recommendations before the Government takes any action.

**श्री राम विलास पासवान :** जी हां ।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: That means that it is really in cold storage.

**श्री वी रेड्डि वर्मा :** माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सबसिडी गरीब आदमी तक पहुंचाने की सिफारिश की गई थी एक वर्ग में उस संबंध में सरकार ने या योजना कमीशन ने कोई स्पैसिफिक संस्तुति की है। इसके साथ ही यह भी बतायें कि कंज्यूमर्स के लिए नेशनल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव फैडरेशन भी एक बहुत आवश्यक केन्द्रीय संस्था है, उसका नाम इसमें नहीं लिखा है, तो एन० सी०सी०एफ० का नाम इसमें क्यों नहीं लिखा और अमीर आदमी को शहरों में जो इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं कि गांवों के आदमियों को नहीं दी जातीं, तो शहर में क्यों दी जा रही है ? आपने अपने उत्तर में कहा है ।

"To cover other areas predominantly inhabited by weaker sections but with the exception of non-poor sections in such area".

तो फिर शहर के आदमी को इस प्रकार को सुविधाए क्यों दी जा रही हैं ?

**श्री राम विलास पासवान :** सभापति जी, मैंने यह नहीं कहा है कि सरकार की यह अनुशंसा है, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी ने यह अनुशंसा की है जिसमें उसने कहा है कि गरीब आदमी को प्राथमिकता दी जाए । पिछली सरकार ने क्या किया, नहीं मालूम लेकिन आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में जो झुग्गी झोंपड़ी में सवा लाख लोग रहते हैं उनमें रहने वालों को तमाम राशन कार्ड मुहैया किए जाएंगे । तीन महीने की डेट दी गई है और कल भी हम लोग और मुरासोली मारन साहब दिल्ली में घूमे हैं इन इलाकों में और हम लोग देख रहे हैं कि सब गरीबों तक राशन भी पहुंचे और सबको राशन कार्ड सुविधा झुग्गी-झोंपड़ियों में दी जाए ।

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the Hon. Minister whether the Government have any scheme or proposal to extend the coverage of the Public Distribution system by including more essential commodities for supply through the Public Distribution System.

**श्री राम विलास पासवान :** यह विचाराधीन है ।

*266. [*The Questioners (Shri Bhagat Ram Manhar and Shri Bir Bhadra Pratap Singh were absent. For answer* vide *Col* 33 infra].

*267. [*The Questioners (Shri Pramod Mahajan and Shri Ashwani Kumar were absent. For answers* vide *Col* 34 *infra*].

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

---

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### Proposal to convert the Railways into an autonomous/Public Sector company

*266. SHRI BHAGATRAM MANHAR:

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal under Government's consideration to convert the Railways into an autonomous body or pubiic sector company;

(b) whether it is also a fact that such a proposal is likely to make the operations of the Railways commercially viable and efficient:

(c) if so, the details in this regard; and

(d) whether any study has been conducted on the said proposal and if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) The proposal to convert the Railways into an autonomous body or public sector company was examined by the Railway Reforms Committee. They recommended that Railways should continue to function as a Department of the Central Government.

### Setting up of Consumer Protection Forums

*267. SHRI PRAMOD MAHAJAN:

SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the State-wise break-up of the District Consumer Protection Forums and State level Commissions established and working effectively so far;

(b) the details of Government's New Action Plan for consumers protection if any, to activate the District Forums and State Commissions in all the districts and States, respectively; and

(c) whether any of the Government services have been exempted from the purview of the Act; if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) According to information available with Central Government, the redressal agencies under the Consumer Protection Act, 1986 have been started and functioning in 15 States/UTs namely Andhra Pradesh (State Commission and 23 District Forums), Bihar (State Commission and I District Forum), Gujarat (State Commission and 3 District Forums), Goa (1 District Forum), Haryana (State Commission and 2 District Forums), Himachal Pradesh (1 District Forums), Maharashtra (State Commission and 1 District Forum), Orissa (State Commission and 13 District Forums), Rajasthan (State Commission and 6 District Forums), Uttar Pradesh (State Commission and 12 District Forums), West Bengal (State Commission and 3 District Forums), Andaman & Nicobar Islands (2 District Forums), Chandigarh (State Commission and 1 District Forums), Delhi (State Commission and 1 District Forum) and Pondicherry (State Commission and 1 District Forum).

(b) The Central Government is coordinating and pursuing the implementation of the Consumer Protection Act in all